



राजस्थान सरकार

युवा शक्ति को अवसर राजस्थान को नई उड़ान



निष्पक्ष, पारदर्शी और पेपर लीक रहित भर्तियां

रोजगार, कौशल विकास, भर्ती, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से युवाओं के सशक्त भविष्य का निर्माण

रोजगार एवं भर्ती

- 1 लाख 78 हजार सरकारी पदों पर नियुक्तियां
- 51,427 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण- भर्ती प्रक्रियाधीन
- 81,023 पदों पर भर्तियों की परीक्षा
- 70,031 पदों पर भर्ती की तैयारी

टेक्नोलॉजी एवं भविष्य

- राजस्थान AI-ML पॉलिसी लागू
- AVGC-XR पॉलिसी से एनीमेशन, गेमिंग और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा
- Rajasthan Digi Fest 2026 का सफल आयोजन

पारदर्शी भर्ती

- भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी का गठन
- 569 आरोपियों की गिरफ्तारी, 157 एफआईआर दर्ज
- 410 भर्ती परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित

उच्च शिक्षा एवं अवसर

- PRIME योजना से मेधावी विद्यार्थियों को रिसर्च और इंटरनशिप के अवसर
- Apprenticeship Embedded Degree Program (AEDP) शुरू
- EV, Renewable Energy, BFSI, HR और Tourism जैसे नए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम शुरू

कौशल विकास एवं शिक्षा

- 3.58 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- 76 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित
- 88,724 विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप वितरण
- 42,509 युवाओं को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ

खेल एवं युवा सशक्तिकरण

- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन
- मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना लागू
- राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोटेंशियल (RTOP) योजना शुरू

युवा कल्याण

- Rajasthan Coaching Centres (Control & Regulation) Bill लागू
- माय भारत पोर्टल पर 19.40 लाख से अधिक युवा पंजीकृत, देश में दूसरा स्थान

स्टार्टअप एवं नवाचार

- राज्य में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 8,780
- स्टार्टअप निवेश ₹250 करोड़ से बढ़कर ₹1,054 करोड़
- 9 इंक्यूबेशन सेंटर और 65 लॉन्चपैड स्थापित
- 1,062 स्टार्टअप्स को ₹33.94 करोड़ की फंडिंग

जो खुद पंजाब में खेमेबाजी में लगे हैं, वो राजस्थान में पार्टी में एकता कैसे लाएंगे?

पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस में सभी को यही चिंता सता रही है

-रेणु मि्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव एस.एस. रंधावा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल लिया है। रंधावा जयपुर आने वाले हैं, जहां उन्हें विभिन्न जिलों में आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच एकता कायम करने की कोशिश करनी है।
रंधावा राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के पूर्ण समर्थन में है। दोनों जाट हैं और दोनों मिलकर राज्य में दूसरे समुदायों को पीछे धकेल कर जाटों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।
लेकिन अपने गृह राज्य पंजाब में रंधावा असहमति, गुटबाजी और खींचतान के केन्द्र बन गए हैं और उन्होंने पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
राजस्थान के कांग्रेस नेता अब उन पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं।

- चिंता का विशेष कारण यह है कि रंधावा, चूंकि राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए राज्य के पंचायत चुनावों में टिकट वितरण की जिम्मेवारी उन्हीं पर रहेगी।
- चर्चा है कि पंजाब में रंधावा, अमित शाह से मुलाकात के बाद चन्नी के साथ मिलकर पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं।
- यह भी चर्चा थी कि पंजाब में उनके बगावती तेवरों के कारण उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा, पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन पर वेणुगोपाल का हाथ है।

उनका सवाल है कि जब रंधावा खुद राजस्थान और पंजाब, दोनों राज्यों में एक-एक गुट के नेता बने हुए हैं, तो वे कांग्रेस के विभिन्न गुटों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं।
राजस्थान कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है : अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली, सचिन पायलट और इसी तरह

के कई अन्य गुट हैं।
सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट बांटने के मामले में रंधावा सभी के साथ न्याय कर पाएंगे।
नेताओं का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए यह चुनाव बेहद

महत्वपूर्ण है। चूंकि भाजपा हर दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस के पास अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। लेकिन पार्टी नेतृत्व का अभी राज्य के मुद्दों पर ध्यान नहीं है।
रंधावा के पाला बदलने, और कथित तौर पर अमित शाह के कहने पर पीसीसी अध्यक्ष राजा के बजाय चन्नी का साथ देने के बाद, जोरदार चर्चा थी कि उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जा सकता है।
लेकिन अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यह है कि उनके साथ क्या किया जाएगा?
और इसके अलावा, वेणुगोपाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं।
रंधावा का जयपुर दौरा, जो कल होना था, अब 17 तारीख तक टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वे खुद को एक ऐसे निष्पक्ष और निर्गुट नेता के रूप में पेश कर पाते हैं, जो सिर्फ जाट नहीं, बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ न्याय कर सके।

- **वी हैव लैफ्ट इट- राहुल।**
- **गतिरोध वैसे का वैसे बरकरार।**

ही संसद के दोनों सदनों में नहीं आए। काफी आलोचना और खराब प्रचार के बाद, अमित शाह जाहिर तौर पर इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री डरे हुए हैं और छात्रों पर पैलेंट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल पर विपक्ष के हमले का सामना नहीं करना चाहते।
सवाल वही हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं हैं।
राहुल गांधी ने इस पेशकश को नज़रअंदाज़ कर दिया है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश को किसी भाषण की जरूरत नहीं है।
वे पहले सवाल का जवाब चाहते हैं और उसके बाद बहस।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

रहस्यमय ढंग से आरोप लगे और रहस्यमय ढंग से हट गए

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने गौतम अडानी को बरी करते हुए कहा, अमेरिकी अभियोजक अपराध साबित करने में विफल रहे और सरकार ने खुद अडानी के खिलाफ मामला खत्म कर दिया

- अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी एजेंसियों ने इसलिए अडानी के खिलाफ अभियोजन आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वे अमेरिका में दस बिलियन डॉलर की पूँजी लगाने वाले हैं और इसीलिए उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है।
- न्याय विभाग ने यह भी कहा कि यह मामला “नाम खराब करने और शर्मिंदा करने” की कोशिश थी। यह भारतीय कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी कंपनियों को बदनाम करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है।

अडानी के खिलाफ मामला नवंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के अंतिम दिनों में शुरू किया गया था।
इस मामले से यह बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि किसी न्यायिक प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों से जुड़े आरोपों वाले केस को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों ने कभी भी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अदालत में अपना पक्ष नहीं

रखा। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उनके ऐसा करने की संभावना भी नहीं थी।
मुख्य आरोप यह था कि अडानी 20 करोड़ डॉलर से अधिक की एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को भारी रिश्वत देने की योजना बना रहे थे। हालांकि, सरकारी वकील सुनवाई के दौरान रिश्वत के वास्तविक भुगतान को कभी साबित नहीं कर पाया।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने के लिए जेपीसी का रास्ता चुना

सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमन को कठोर बनाने के लिए यह संशोधन किया और इसके लिए वह हितधारकों की चिंताओं और राजनैतिक प्रभावों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार द्वारा फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक), 2026 को जाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को और कड़ा करते हुए, संसदीय गतिरोध, हितधारकों की चिंताओं और राजनीतिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से एफसीआरए, 2010 में संशोधन करना है। इसके तहत, एक निर्दिष्ट प्राधिकरण (डेंजिमेंटेड

- सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का मुख्य आधार बताया है।
- विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अर्था(रटी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से वापस लिए जाने या उसकी अवाधि समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन तथा निपटान करेगा।
सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य उन प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके कारण अनिश्चितता और संभावित दुरुपयोग की स्थिति पैदा

होती है। इसके तहत, संपत्तियों को अस्थायी रूप से सरकार के अधिकार में रखने और संगठन का पंजीकरण दोबारा बहाल होने पर उन्हें वापस करने का प्रावधान होगा। साथ ही, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने और, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना, सभी संगठनों पर नियम समान रूप से लागू करने की बात कही गई है।
(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। “बार एंड बेच” की रिपोर्ट के अनुसार, “रलोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू” ने बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.

- यूक्रेन के ओशादबैंक के साथ विवाद पर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ को अपना प्रतिनिधि बनाया है।

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज शेयरधारकों के साथ तनाव और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ अपना कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मतभेदों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में कहा कि अगले साल फरवरी में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर वे दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।
चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।
उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस की

- चंद्रशेखरन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का फैसला किया था और टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रैगुनेरेशन कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया था।
- पर, जब 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो एक सदस्य ने समर्थन नहीं दिया और सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने से मैंने इसे तब टाल दिया और अब 6 माह बाद भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो मैंने यह निर्णय लिया है।

नॉमिनेशन एण्ड रैगुनेरेशन कमेटी तथा बोर्ड ने भी इसे रिर्काई किया और इसकी सिफारिश की। इसके बाद यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि बोर्ड के एक सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने के कारण मैंने इस फैसले को टालने का निर्णय लिया।”

चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की बैठक को छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।
उन्होंने कहा, “टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं इस समय बेहद अहम चरण में हैं। यह जरूरी है कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की नियुक्ति हो।

साथ ही नेतृत्व को लेकर स्पष्टता कर्मचारियों, निवेशकों, पार्टनर्स और अन्य स्टैक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।”
चंद्रशेखरन पिछले 40 वर्षों से टाटा समूह का हिस्सा रहे हैं। वे जनवरी 2017 से टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और 2009 में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने टाटा संस की कमान संभाली।
उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने के बेहद संतोषजनक अवसर के लिए आभारी हूं। पिछले एक दशक में टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान और गहरी जिम्मेदारी का विषय रहा है।”
अपने उत्तराधिकारी की प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में चंद्रशेखरन ने

ऑटो -टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

- सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया है, भाषा नहीं जानने पर तीन माह तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया।

है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में

‘जल्दी आयेगा जंतर मंतर सीजन -2’

नई दिल्ली, 12 अगस्त। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर के सीजन-2 को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि जंतर-मंतर का सीजन-2 जल्दी ही आएगा।
अभिजीत दीपके ने कहा, बहुत से लोग इस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि जंतर-मंतर का सीजन 2 कब शुरू

- **कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने घोषणा की।**

होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जंतर-मंतर का सीजन 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वे लोग उन्हें वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल नहीं मिलने दे रहे। दीपके ने आज बुधवार को कहा कि आज दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट होनी थी, दूर-दूर से हमारी पार्टी से जुड़े लोग आए थे, लेकिन हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही।

‘घर-घर जाके कूड़ा उठाने की टेंडर प्रक्रिया में भारी धांधली!’

राजस्थान हाई कोर्ट ने टेंडर रद्द करने के आदेश दिए

- हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से निविदा की शर्तों में फेर बदल किया गया है उससे जाहिर है कि एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी और अन्य निविदाकारों को भाग लेने से वंचित करने का षड़यंत्र भी रचा जा रहा था।
- हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि जिन शर्तों पर पहले निविदा जारी की गई थी, उन्हीं शर्तों पर निविदा जारी की जाए।
- यह मामला मानसरोवर क्षेत्र में घर घर जाके कूड़ा उठाने से सम्बन्धित है।
- 2025 एवं 2026 में नगर निगम ने निविदा आमंत्रित की, जिसमें याचिकाकर्ता रवि ट्रैवल्स भाग ले चुके थे, परन्तु दोनों निविदाओं को नगर निगम ने अकस्मात ही रद्द कर दिया और 2026 में ही ऐसी निविदा जारी की, जिससे याचिकाकर्ता व अन्य निविदाकार भाग ही न ले सकें। शर्त यह थी कि निविदाकार के पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, जिसकी रजिस्ट्री केवल 2026 की हो।

जाके कचरा उठाने का टेंडर मिला था। उसे यह टेंडर एक वर्ष के लिए मिला था, जिसमें नगर निगम को लगभग 12.85 करोड़ की लागत उठानी थी। उल्लेखनीय है कि इस मामले के

तथ्यों के अनुसार, नगर निगम ने 2025 में पुनः एक टेंडर जारी किया उक्त क्षेत्र से कचरा उठाने के लिए जिसमें नगर निगम द्वारा शर्त रखी गई कि केवल वो ही निविदाकार भाग ले पाएंगे, जिनके

पास ऐसी गाड़ियां हो जो कम से कम 900 किलो कूड़ा उठाने का भार उठा सके। शर्त के अनुसार, ये गाड़ियां जनवरी 2024 से पहले की रजिस्टर्ड गाड़ियां नहीं होनी चाहिए और सभी

गाड़ियां निविदाकार के नाम पर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 2025 में ही याचिकाकर्ता ने 18 करोड़ की लागत से 90 नई गाड़ियां खरीदी थीं इसलिए वह इस निविदा में भाग लेने के

लिए उपयुक्त है। परन्तु हैरानी की बात है कि 20 फरवरी 2026 को नगर निगम ने उक्त टेंडर को रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए और कोई कारण भी नहीं बताया। उल्लेखनीय है कि एक महीने बाद ही 12 मार्च 2026 को नगर निगम ने उन्हीं शर्तों के साथ पुनः निविदा आमंत्रित करी। परन्तु दो ही महीने बाद 9 अप्रैल 2026 को इस निविदा को भी रद्द कर दिया और रद्द करते हुए नोटिस में केवल यह जानकारी दी कि निविदा को “अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है”। तत्पश्चात नगर निगम ने 4 जून 2026 को पुनः एक नई निविदा आमंत्रित की परन्तु इसमें यह शर्त लगा दी कि निविदाकार के पास ऐसी गाड़ियां होनी चाहिए, जिनकी रजिस्ट्री जनवरी

2026 से पहले की हो।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि तीसरी निविदा की शर्तों में मनमाने तरीके से फेर- बदल केवल

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

निजी पूंजी जुटाने में विकास बैंकों की भूमिका अहम: सीतारमण

जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की दो दिवसीय बैठक आयोजित

जयपुर। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख इंजन हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाने के मामले में सदस्य देशों के सामने कई समान संरचनात्मक चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि चुनौती केवल पूंजी उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए भरोसेमंद, स्थिर और पूर्वानुमेय

■ ‘ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास की प्रमुख इंजन, निवेशकों का भरोसा और स्थिरता जरूरी’

माहौल तैयार करने की भी है। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंक के गर्वनरों की बैठक के दौरान द रोल ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मंबर कंट्रीज विषय पर आयोजित सेमिनार में सीतारमण ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने विकास परियोजनाओं के लिए निजी पूंजी जुटाने में बहुपक्षीय विकास बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करना चाहिए। भारत सरकार ने इसी सोच के तहत बुनियादी ढांचे और निवेश को



केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गर्वनरों की बैठक को संबोधित किया।

बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (बीजीएफ), हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, क्रेडिट बढ़ाने वाले उपाय, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ परियोजनाओं में तालमेल और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद की है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई लांशत प्रावधान किए गए हैं। इनमें नए डेडिक्टेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, नए राष्ट्रीय जलमार्ग

और तटीय मार्गों प्रोत्साहन योजना प्रमुख हैं। इन पहलों का उद्देश्य देश में लॉजिस्टिक्स और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के साथ निजी निवेश के नए अवसर तैयार करना है। सीतारमण ने भारत के बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने लगातार सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना इकोसिस्टम को मजबूत किया है। पिछले एक दशक में राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स प्रणालियों, डिजिटल अवसंरचना और ऊर्जा नेटवर्क में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि विकासात्मक वित्त का भविष्य साझेदारी में निहित है। बहुपक्षीय संस्थाओं, राष्ट्रीय

सरकारों और निजी क्षेत्र की अपनी-अपनी विशिष्ट क्षमताएं हैं। इनके बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी जुटाकर विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती है।इससे पहले आर्थिक कार्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने स्वागत भाषण में कहा कि विकासात्मक वित्त के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने के साथ-साथ मजबूती और दीर्घकालिक स्थिरता भी जरूरी है। सेमिनार में बहुपक्षीय संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, निजी कंपनियों, थिंक टैंक और अकादमिक जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बाद में निजी पूंजी जुटाने और विकास वित्त से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत पैनल चर्चा भी हुई।

दो तस्कर गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरे की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन आग के तहत हरमाड़ा और मासरोवर थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है।

192 गांवों में जल्द बनेंगे अटल प्रगति पथ

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर प्रदेश में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ कर ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने गांवों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में 5 हजार से अधिक आबादी के शेष 192 गांवों में भी अटल प्रगति पथ के निर्माण के लिए 381.91 करोड़ रूपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति से 28 जिलों के 192 गांवों एवं आबादी क्षेत्रों में करीब 286 किलोमीटर सड़क निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हो सकेंगे।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का प्रत्येक गांव और आबादी क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़े और विकास का लाभ अंतिम छोर तक सुगमता से मिल सके। उन्होंने कहा है कि सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली आधारभूत कड़ी है।

बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें : जोराराम कुमावत

जयपुर। पशुपालन, डेयरी गोपालन एवं देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय के चिंतन कक्ष में पशुपालन विभाग एवं डेयरी की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की गई। कुमावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाएं प्रदेश के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखकर की गई हैं, इसलिए इनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रत्येक घोषणा की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति से

■ बैठक में तीन वर्षों की बजट घोषणाओं की वर्तमान स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा उनके समयबद्ध निष्पादन पर विस्तृत समीक्षा की

संबंधित प्रस्तुतीकरण दिया तथा निर्माणधीन परियोजनाओं, नवीन पशु चिकित्सालयों, पशु चिकित्सा उपकेंद्रों, मोबाइल वेटनरी यूनिट, पशुधन विकास, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान, पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं अन्य योजनाओं की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक सुविधाएं एवं गुणवत्तापूर्ण पशुपालन अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कार्यों में किसी प्रकार की बाधा आ रही है, उनका शीघ्र समाधान कर कार्यों में अपेक्षित गति लाई जाए। उन्होंने सभी स्तर के चिकित्सा

संस्थाओं के पट्टे जल्द से जल्द हासिल करने पर बल देते हुए कहा कि हर संस्थान के पास अपना भवन होना चाहिए जिससे पशुओं को बेहतर चिकित्सा मिल सके। कुमावत ने भेड़ ऊन विभाग की जमीन को भी पशुपालन विभाग के अंतर्गत शामिल करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मंत्री कुमावत ने डेयरी की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक दुग्ध सहकारी समितियां और दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन उत्पादों की मांग अधिक है उनका गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने बस्सी में स्थित सेक्स सर्टिड सीमन उत्पादन इकाई की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार की बजट घोषणाएं केवल घोषणा मात्र नहीं हैं इससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों का सशक्तीकरण होता है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए इन घोषणाओं का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी क्रियान्वयन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

पशुपालन विभाग में 113 कार्मिकों को मिला पदोन्नति का तोहफा

जयपुर। पशुपालन विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग की सभी श्रेणियों की पदोन्नति प्रक्रिया वर्ष 2025-26 तक पूर्ण कर दी है। विभाग द्वारा आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पश्चात विभिन्न पदों पर कुल 113 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है जिनमें संस्थापन अधिकारी के 05, प्रशासनिक अधिकारी के 16, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 34 तथा वरिष्ठ सहायक के 20 पद हैं।विभाग की ओर से पदोन्नति प्रक्रिया को निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप समयबद्ध रूप से संपन्न किया गया है।इससे मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को उनकी योग्यता, अनुभव एवं सेवा अवधि के अनुरूप पदोन्नति का लाभ प्राप्त हुआ है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीणा ने कहा कि मंत्रालयिक संवर्ग के सभी वर्गों की पदोन्नति वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाना विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पदोन्नति प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए गए। उन्होंने सभी पदोन्नत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि कार्मिक किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।



निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

कहा कि युवा मतदाताओं के आवश्यक रूप से अपना मतदाता पहचान-पत्र बनवाना चाहिये और आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिये। साथ ही अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों और पंचायतों में जनता को स्वयं जागरूक होकर निष्पक्ष और स्वच्छ छवि के आधार जन प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए।कार्यक्रम में महाविद्यालय के निर्वाचन साक्षरता क्लब () की ओर से वर्षभर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। ईपूलसी प्रभारी प्रो. गोविन्द शरण शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में युवाओं को चुनावी प्रक्रिया तथा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के प्रति जागरूक करने के लिए निबंध, कविता पाठ, पोस्टर एवं रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

ओपन जेल के कैदी की गोली मारकर हत्या

जयपुर। करणी विहार थाना क्षेत्र के धावास स्थित जानकी विहार इलाके में बुधवार को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने ओपन जेल के कैदी मोहन कुमावत (40) की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने मोहन पर तीन राउंड फायर किए और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कराकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल और आसपास के रास्ते पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। सामने से मौका मिलते ही उन्होंने मोहन को निशाना बनाकर फायरिंग की। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर करणी विहार के साथ भोंकरोटा और चित्रकूट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य

- बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने तीन राउंड फायर किए
- जेल लौटते समय धावास के जानकी विहार में वारदात

जुटाए और शव को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जांच में सामने आया कि मोहन कुमावत 2018 में मोती डूंगरी इलाके में महेंद्र गुर्जर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और उसे सजा हुई थी। वर्तमान में वह सांगानेर स्थित ओपन जेल में बंद था। बुधवार को वह जेल लौट रहा था। इसी दौरान धावास के जानकी विहार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने उसका पीछा कर उसे निशाना बनाया।



जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री सीएलजी सदस्यों से आज संवाद करेंगे

जयपुर। प्रदेश में कानून-व्यवस्था, सामाजिक सीहार्द और पुलिस-जन सहभागिता को मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस ने कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) को प्रभावी बनाने की पहल शुरू की है। इसके तहत गुरुवार को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्यस्तरीय ओरिएंटेशन एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशभर के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे शुरू होगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जयपुर रेंज के सभी पुलिस थानों के नव-नियुक्त सीएलजी सदस्यों को बिड़ला ऑडिटोरियम में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट ने द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमण व जुड़े मुकदमों की जानकारी मांगी

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी में हुए अतिक्रमणों की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पौन मंडोला की जनहित याचिका सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए द्रववती नदी को दूषित बताया और साथ ही कहा की शहर में इंंदौर के मुकाबले गंदी अधिक है।

■ अदालत ने जेडीए से 31 अगस्त तक बताने को कहा है कि यहां की जमीन से जुड़े मुकदमें किस-किस कोर्ट में किस स्तर पर चल रहे हैं

अदालत को कहा कि उनकी ओर से गत फरवरी माह में रिपोर्ट देकर कई कमियों को उजागर किया था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यदि रिपोर्ट में कोई कमी है तो उसे बलाए, वरना रिपोर्ट पर कार्रवाई करें। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस पर अपना रिसर्प्स पेश करने के लिए समय मांगा। जिस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए

कहा कि 6 माह बाद भी सरकार समय ही मांग रही है। ऐसे में सरकार को अंतिम मौका दिया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता पीएन मैदोला ने उपस्थित होकर कहा कि नदी क्षेत्र की जमीन के कई खसरो पर अतिक्रमण हो गया है और जेडीए कईयों का नियमन भी कर रहा है। इस पर जेडीए के अधिवक्ता ने कहा कि जेडीए की ओर से अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा कई लोग विभिन्न अदालतों में जाकर स्थान आदेश ले आते हैं। इस पर खंडपीठ ने जेडीए को यहां के अतिक्रमण और मुकदमों की जानकारी पेश करने के आदेश देते हुए राज्य सरकार को न्यायमित्र की रिपोर्ट पर अपना रिसर्प्स पेश करने के आदेश दिए हैं।

दुष्कर्म आरोपी समेत हुक्का बार संचालक गिरफ्तार

जयपुर। बजाज नगर थाना पुलिस ने अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को वारदात के 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं गोपालपुरा मोड़ स्थित एक रेस्तरां में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर दबिश देकर दो संचालकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर बरामद किए।

पाइप और विभिन्न फ्लेवर जब्त किए। डीसीपी जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई थी। एडीसीपी पारस मल जैन और एसपी मालवीय नगर विनोद कुमार शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी रामधन ढोबाल के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने तकनीकी सहायता और लगातार

प्रयासों के बाद अंकित कुमार (26) निवासी निमभोड़ जिला कोटपूतली-बहरोड़ को 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया।दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने गोपालपुरा मोड़ स्थित फिन रेस्तरां कैफे पर दबिश दी। जांच के दौरान कैफे में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित होना पाया गया। पुलिस ने मौके से चार हुक्के, चिलम, पाइप और विभिन्न फ्लेवर बरामद किए।

राज्य में “ 2 0 4 7 तक सभी के लिए बीमा ” के लिए तैयारियां शुरू

जयपुर। ‘ 2047 तक सभी के लिए बीमा ’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रशासनिक तंत्र ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस सम्बंध में बुधवार को मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास और भारतीय बीमा वित्तियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) चैयरमैन श्री अजय सेठ के बीच शासन सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में वित्त (व्यय) सचिव डॉ. टीना सोनी भी उपस्थित रही।



मुख्य सचिव और आईआरडीएआई चैयरमैन के बीच रोडमैप के बारे में चर्चा हुई।

बैठक में असंगठित और वंचित वर्गों के बीच बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दुर्घटना एवं जीवन बीमा कवरेज के विस्तार पर चर्चा हुई। दोनों ने स्वास्थ्य दावों के त्वरित निस्तारण करने की सम्भावना पर विचार किया जिससे दावेदारों को समय पर राहत मिल सके। बैठक में लिए निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य बीमा एवं

साधारण प्रावधानी निधि विभाग श्रीधर शर्मा की समन्वित विभागों, एजेंसियों और अन्य स्टैकहोल्डर्स की बैठक आयोजित करा। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष , राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, एसआईपीएफ निदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, अस्पताल संघों के प्रतिनिधि और प्रमुख बीमा प्रदाताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

राज्य भर में वाणिज्यिक वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज अनिवार्य करने के उपायों पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव और आईआरडीएआई अध्यक्ष ने मोटर वाहन दुर्घटना दावों के लम्बित मामलों का लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित निस्तारण करने की सम्भावना पर विचार किया जिससे दावेदारों को समय पर राहत मिल सके। बैठक में लिए निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य बीमा एवं

नवाचारों के साथ विद्यार्थियों के कौशल विकास को मिले प्राथमिकता : एसीएस

शिक्षा के क्षेत्र में विकास कार्यों, नवाचारों एवं कार्ययोजना पर मंथन

जयपुर। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में पीरामल फाउंडेशन ग्रुप के चैयरमैन अजय पीरामल, सीईओ आदित्य नटराज, मोतीलाल ओसवाल फाइनंशियल सर्विसेस लिमिटेड के चैयरमैन एवं सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल के साथ राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों, नवाचारों, मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने एवं भावी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल, रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का वातावरण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में यादव ने प्रदेश में संचालित विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं, सरकारी विद्यालयों एवं शिक्षा कार्मिकों से संबंधित जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 649 पीएमविद्यालयों की तरह सीएम राइज



अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बुधवार को जयपुर में भावी कार्ययोजना को लेकर चर्चा की।

में 400 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ नवाचारों को बढ़ावा देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा सेतु कार्यक्रम की जानकारी देते हुए इसके माध्यम से

विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं एवं विद्यालयी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। एससीएस ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाएं। उन्होंने विद्यालयों में संचालित

■ एआई, डिजिटल तकनीक से स्मार्ट शिक्षा और मॉडल स्कूलों से सशक्त होगी राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था

व्यावसायिक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का विस्तार करने तथा दूरस्थ एवं छोटे गांवों के विद्यालयों तक इनका लाभ पहुंचाने की आवश्यकता बताई। बैठक में विद्यार्थियों एवं युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संस्थागत स्तर पर कार्यक्रम संचालित करने, ड्रापआउट रोकने, नियमित उपस्थिति बढ़ाने तथा कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर भी विचार-विमर्श हुआ। विद्यालयों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए फाइनंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई। चयनित सरकारी विद्यालयों को

बेहतर सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाते हुए मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने तथा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। पीरामल फाउंडेशन के संस्थापक अजय पीरामल ने संस्था द्वारा राजस्थान में किए जा रहे कार्यों का फीडबैक लिया तथा चर्चा एवं सुझावों के अनुरूप सहयोग को और बढ़ाने का आश्वासन दिया। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा के तहत संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं, जेंडर, हाईजीन, आधारभूत संरचना, राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समयबद्ध तैयारी, योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग तथा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के साथ उनके समग्र विकास, कौशल एवं रोजगार क्षमता पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

